of important crop plants sustainability of farming/cropping system, bio-systematics integrated, nutrient management etc. to promote new technology.

(b) Substantially high allocation of Rs. 215.19 crore has been made for the Institute by the ICAR for the VIII Plan period (7992—97).

(c) Eleven research assignments with foreign collaboration have been undertaken. These relate to phytotron facility, post harvest technology, seeds, varietal improvement, biotechnology integrated pest management etc.

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण-नीति का पालन न किया जाना

***३६९. श्री मूल चन्द मीणा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न विश्व-विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण-नीति का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति के पालनार्थ सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार इस आरक्षण नीति का पालन न करने वाले विश्व-विद्यालयों को दी जा रही सहायता-अनुदान राशि पर रोक लगाने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए समय-समय पर यथा-घोषित आरक्षण नीति को अपनाने की अपेक्षा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालयों को सलाह दी है कि वे सरकार की आरक्षण नीति का पालन करें। तथापि, विश्वविद्यालयों का स्वायत्त स्वरूप होने के कारण, उनका निर्णय लेने का अपना तंत्र है और कुछ विश्वविद्यालयों में आरक्षण सरकार की आरक्षण-नीति के अंतर्गत अपेक्षित सीमा तक नहीं हुआ है। इस मामले की उपयुक्त उपचारी कार्रवाई के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को निधियां प्रदान की जाती है, जो आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों से आग्रह करता रहा हैं।

Release of Funds to Mumbai Mahanagar Palika

*370. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Maharashtra has not transferred the approved aid of Rs. 100 crores sanctioned by the Central Government during 1985 to Mumbai Mahanagar Palika; if so, the reasons therefor;

allocate any ad-hoe grant to the satellite Mahanagar Palika like Thane, Kalyan, Navi Mumbai which are facing indenti-cal problems as that of Mumbai Mahanagar Palika; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) A special grant of Rs. 100 crores was sanctioned in 1987 by the Government of India to the Government of Maharashtra for tackling the problem of slums and housing in Bombay. The projects are to be implemented by various agencies including Bombay Municipal Corporation (BMC). Out of Rs. 100 crores, Rs. 88 crores have been released upto 31st March, 1992 to the Government of Maharashtra for distribution to the implementing agencies on the basis of the progress of works.

(b) and (c) No, Sir. 'Urban Develop ment' is a State subject and the Minis try of Urban Development in the Government of India plays only a nodal role. There are no discretionary funds with the Government of India for giving such grants to any city. The State Governments would have to formulate necessary development projects and get them included in the annual plans in